



ISSN Print: 2394-7500
 ISSN Online: 2394-5869
 Impact Factor: 8.4
 IJAR 2020; 6(2): 269-272
www.allresearchjournal.com
 Received: 04-12-2019
 Accepted: 11-01-2020

डा. श्रीमती संगीता सिंघल
 एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
 विभाग, सनातन धर्म महाविद्यालय,
 मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

शिक्षा और मानव संसाधन विकास

डा. श्रीमती संगीता सिंघल

DOI: <https://doi.org/10.22271/allresearch.2020.v6.i2d.9787>

प्रस्तावना

शिक्षा, प्रगति और विकास की अनिवार्य शर्त है आज के बदलते परिवेश में शिक्षा का सम्बंध मनुष्य और समाज के किसी एक पहलू से ही नहीं है बल्कि इसका सम्बंध मानव के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से है। शिक्षा, सामाजिकरण बदलाव और नवीनता लाने की प्रक्रिया है। यह जन्म से मृत्यु पर्यन्त व्यक्ति के समग्र विकास की कुंजी है। आज सारा विश्व इस बात को मानने लगा है कि हमारे भविष्य को आकार देने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा राष्ट्रीय विकास का आधार है। शिक्षा का स्तर ऊँचा होने से, देश की उत्पादकीय क्षमता व कार्यकुशलता प्रभावित होती है। अतः शिक्षा देश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने का सशक्त माध्यम है। शिक्षा से जहाँ व्यक्ति को विशिष्ट ज्ञान मिलता है, वहीं दूसरी ओर मूल्यों और मान्यताओं में परिवर्तन होने के कारण इससे अपने कार्य और समाज के बारे में व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है।

भारत में मानवीय संसाधन गुणात्मक दृष्टि से उस स्तर के नहीं कहे जा सकते, जिस स्तर की तीव्र विकास की आवश्यकता होती है। शिक्षित व प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव, कार्यशील जनसंख्या का निम्न अनुपात व कुपोषण तथा जीवन-यापन की असंतोषजनक दशाओं के कारण उत्पादकता का निम्न स्तर है, आदि हमारे मानवीय संसाधनों की विशेषताएँ हैं, जो देश के विकास के मार्ग में बाधा का कार्य करती हैं। माननीय संसाधनों से हमारा तात्पर्य, उन सभी साधनों से है जो मनुष्य के विकास में सहायक होते हैं इनमें हम शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य चिकित्सा, रोजगार आदि को सम्मिलित करते हैं। मानव संसाधन विकास, किसी भी देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है जब तक मानवीय संसाधनों का विकास नहीं होगा, जब तक देश का विकास भी सम्भव नहीं होगा।

प्रो० सी०एन० माथुर "यह समझना गलत होगा कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राष्ट्र शैक्षणिक प्रगति कर ही नहीं सकता।" राष्ट्र के सुयोग्य संयोजक, जिम्मेदार शिक्षक, अधिकारी उत्साही अध्यापक और परिश्रमी छात्र इस अर्थाभाव की "पूर्ति में एक सीमा" तक समर्थ हो सकते हैं, किन्तु योग्य और चरित्रवान कार्यकर्ताओं का आयात नहीं किया जा सकता। इन्हें तो राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा ही हमें पैदा करना है। अतः यदि हम देश में उपलब्ध मानवीय एवं प्रकृतिक सम्पदा का उचित उपयोग करके राष्ट्रीय विकास की गति को तेज करना चाहते हैं तो हमें शिक्षा को मानवीय उद्योग स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

यह अत्यन्त खेद का विषय है कि भारत में मानवीय संसाधनों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। आज भारत में मानव विकास को प्रोन्नत करने की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः सरकार को शिक्षा व स्वास्थ्य में विनियोग करना होगा। हमारी शिक्षा का दुखद पहलु यह है कि देश में शिक्षा के माध्यम से जो मानव शक्ति का निर्माण किया जा रहा है वह हमारी आर्थिक विकास की योजनाओं के अनुरूप नहीं है। मानवीय संसाधन विकास को उन्नत करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य से सम्बन्धित सुविधाओं और सेवाओं में निवेश करना अनिवार्य और आवश्यक है। सरकार की अर्थपरक सोच, उच्च शिक्षा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है? पिछले कुछ वर्षों से आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा पर की जाने वाली निवेश की राशि लगातार घटती जा रही है जबकि आवश्यकता, निवेश को बढ़ाकर अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित करने की है। आज यह महसूस किया जा रहा है कि, राष्ट्र की सुदृढता व विकास के लिए शिक्षा की संरचना में पुनः सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। आर्थिक स्वतन्त्रता के इस प्रतिस्पर्धी युग में हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो मानवीय संसाधनों का विकास देश की आवश्यकताओं के अनुरूप करें।

प्रस्तुत शोध पत्र में शिक्षा, मानवीय संसाधन विकास में किस प्रकार से सहायता कर सकती है तथा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा, तकनीकी व स्वास्थ्य पर किस प्रकार से व्यय किया गया है, आँकड़ों की सहायता से अवगत किया गया है।

Corresponding Author:
 डा. श्रीमती संगीता सिंघल
 एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
 विभाग, सनातन धर्म महाविद्यालय,
 मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

शिक्षा प्रगति और विकास की अनिवार्य शर्त है। आज बदलते परिवेश में शिक्षा का सम्बंध मनुष्य और समाज के किसी एक पहलू से नहीं है बल्कि इसका सम्बंध मानव के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से है। शिक्षा, सामाजिकरण और नवीनता लाने की प्रक्रिया है। यह जन्म से मृत्युपर्यन्त व्यक्ति के समग्र विकास की कुंजी है। आज सारा विश्व इस बात को मानने लगा है कि हमारे भविष्य को आकार देने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा राष्ट्रीय विकास का आधार है। इस प्रकार शिक्षा राष्ट्रीय विकास के लिए नींव का कार्य करती है। अतः जितनी पूंजी शिक्षा क्षेत्र में निवेश की जायेगी, उतना ही देश का आर्थिक विकास होगा। मेयर के अनुसार शिक्षा राष्ट्रीय विकास का बीज एवं फूल है।

सामान्य आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि के आधार पर देखा जाता है, आर्थिक विकास एक कल्याणकारी अवधारणा है जिसका शिक्षा से घनिष्ठ सम्बंध है। देश में शिक्षा का स्तर अच्छा होने से उस देश की उत्पादकीय क्षमता, कार्यकुशलता प्रभावित होती है।

अतः शिक्षा, देश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने का सशक्त माध्यम है। शिक्षा से जहाँ व्यक्ति को विशिष्ट ज्ञान मिलता है वहीं दूसरी ओर मूल्यों और मान्यताओं में परिवर्तन होने के कारण इससे जहाँ अपने कार्य और समाज के बारे में व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसम्पत्ति के रूप में देखते हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या संसाधन के रूप में बदल जाती है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। मानव संसाधन से हमारा तात्पर्य उन सभी साधनों से है जो मनुष्य के विकास में सहायक होते हैं। इनमें हम शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार आदि को सम्मिलित करते हैं। मानव संसाधन विकास किसी भी देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जिस देश में मानव संसाधनों का प्रयोग उचित ढंग से किया जाता है वह देश अन्य देशों की तुलना में अधिक विकास करता है।

मानव संसाधन विकास के आवश्यक तत्व

प्रो० शुल्ज ने मानव संसाधन के विकास के चार तरीके बताये हैं

- ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना जो लोगों की जीवन प्रत्याशा, शक्ति, उत्साह व कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकें।
- कार्य शिक्षण को बढ़ावा देना।
- प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था करना।
- व्यस्कों के लिए शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

शिक्षा: एक विनियोजन

शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय पर विचार करना अति आवश्यक है, शिक्षा में विनियोग की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में ऐसे गुण तथा क्षमताएँ आ जाती हैं जो स्वयं अपने लिए तो धन कमाते ही हैं साथ ही देश के उत्पादन प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं।

आज अधिकांश विकासवादी अर्थशास्त्री इस बात के पक्षधर हैं कि मानव-पूंजी में अधिक से अधिक विनियोग किया जाना चाहिए, ताकि अर्थिक विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक मानव संसाधन का समुचित विकास किया जा सके।

प्रो० मेयर के अनुसार "विकास की कुंजी मनुष्य है और तीव्र गति से विकास के लिए मानवीय योग्यताओं, आदर्शों तथा दृष्टिकोणों में परिवर्तन वांछनीय है।" चूंकि आर्थिक विकास पूर्णतया मानवीय

संसाधनों पर निर्भर करता है अतः मानवीय संसाधनों का विकास आर्थिक विकास की पूर्व आवश्यकता समझी जाती है।

प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री शुल्ज का कथन है कि "हमारी आर्थिक प्रधाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण मानव पूंजी का विकास है ऐसे किए बिना हमें व्यापक दरिद्रता एवं कठोर शारीरिक श्रम से मुक्ति नहीं मिल सकती"

प्रो० वी०के० आर०वी० राव के अनुसार "मानव की कुशलता एवं दक्षता पर ही आर्थिक विकास का ढांचा खड़ा किया जा सकता है"

प्रो० जे०के० गैलब्रेथ का विचार है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास में अनेक साधनों के अलावा शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का सर्वाधिक योगदान रहा, अब हमें अपनी औद्योगिक वृद्धि का एक बड़ा भाग अधिक पूंजी के विनियोग से नहीं मिलता, बल्कि वह मनुष्यों में निवेश और परिष्कृत मनुष्यों द्वारा किए गए सुधारों के कारण प्राप्त होता है"

साइन कुजेनेट्स के अनुसार "व्यापक अर्थ में मुख्य पूंजीगत स्टॉक लोगो का प्रशिक्षण, चरित्र एवं कार्यकुशलता है" मानव संसाधन विकास के महत्व को स्पष्ट करते हुए एडम स्मिथ ने विचार व्यक्त किया था कि पूंजी के स्टॉक में सब निवासियों की अर्जित तथा उपयोगी योग्यताओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। नव-प्रतिष्ठित सम्प्रदाय के अग्रणी अर्थशास्त्री मार्शल का भी विचार था कि सबसे मूल्यवान पूंजी वह है जो मानव-मात्र में विनियोजित की जाए।

मानव संसाधन विकास आर्थिक विकास का एक प्रभावकारी एवं सकारात्मक अवयव है। किसी देश के सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ मनुष्यों का निपुण, ज्ञानी और बुद्धिमान होना आवश्यक है।

प्रो० जैफरेन्ज ने कहा है कि आर्थिक प्रगति के लिए लालायित देश जब विकसित देशों से आधुनिक तकनीक और नवीनतम मशीनरी का आयात करके भी विशाल काम प्लांटों को खड़ा करते हैं तभी प्रदा वनजचनज की मात्रा व किस्म प्रायः असन्तोषजनक बनी रहती है। क्योंकि अधिकांश स्थितियों में प्रबन्धक तथा श्रमिक अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं होते हैं और उनमें वांछित अनुभव की कमी होती है। अतः आज के युग में मानव संसाधन विकास में विनियोग किसी भी देश के आर्थिक विकास की एक प्रमुख शर्त बन चुकी है।

मानवीय संसाधनों में विनियोग के क्षेत्र

मानवीय संसाधनों में विनियोग का अर्थ शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य उपयुक्त भोजन और उचित आवास की व्यवस्था आदि पर व्यय करने से है।

स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सेवाएं

स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सेवाओं के अन्तर्गत उन प्रयत्नों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे लोगो के औसत जीवन आयु, शारीरिक शक्ति व योग्यता, काम करने की इच्छा व प्रेरणा आदि में वृद्धि होगी। मानवीय साधनों की कार्यक्षमता और कुशलता शारीरिक योग्यता पर निर्भर करती है। सन्तुलित भोजन व अन्य जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं के उपलब्ध न होने पर श्रमिकों में शारीरिक दुर्बलता आती है उससे उत्पादकता कम हो जाती है। परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में कमी होने लगती है। अतः इस दृष्टि से आवश्यक है कि लोगो की स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सेवाओं को उच्च स्तर पर बनाये रखने के लिए इस क्षेत्र में विनियोग किया जाना चाहिए।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाएं

प्रो० रिचर्ड टी० गिल के अनुसार "शिक्षा पर किया गया विनियोग आर्थिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक विनियोग माना जाये"

प्रो० सी०एल० माथुर के अनुसार “यह समझाना गलत होगा कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राष्ट्र शैक्षणिक प्रगति कर ही नहीं सकता। राष्ट्र के सुयोग्य संयोजक, जिम्मेदार शिक्षक, अधिकारी, उत्साही अध्यापक और परिश्रमी छात्र इस अर्थाभाव की पूर्ति में एक सीमा तक समर्थ हो सकते हैं किन्तु योग्य और चरित्रवान कार्यकर्ताओं का आयात नहीं किया जा सकता। इन्हें तो राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा ही हमें पैदा करना है। अतः यदि हम देश में उपलब्ध मानवीय एवं प्राकृतिक सम्पदा का उचित उपयोग करके राष्ट्रीय विकास की गति को तेज करना चाहते हैं तो हमें समक्ष शिक्षा को मानवीय स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।” प्रो० सिंगर के अनुसार, “शिक्षा में किया गया विनियोग केवल उत्पादक ही नहीं होता बल्कि यह वर्धमान प्रतिफल भी करता है” यही कारण है कि विकसित देशों द्वारा अपने आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को अत्याधिक महत्व प्रदान किया जाता है।

भारत के संदर्भ में डा० राव कहते हैं कि “आज हमारे देश पर चरित्र संकट मंडरा रहा है, इसका मुकाबला हम केवल इस तरह की शिक्षा देकर कर सकते हैं जो मानवता और चरित्र निर्माण की दिशा में प्रवृत्त हो। निःसंदेह अर्थव्यवस्था की अवस्थाएं पूरी करना शिक्षा का कर्तव्य है। हमारे विश्वविद्यालयों में उन कौशल और मनोवृत्तियों तथा अनुसंधान कार्यों को प्रश्रय दिया जाना चाहिए, जिनकी हमारी सुनियोजित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूरी करने तथा आर्थिक वृद्धि की दर तीव्रतर करने के लिए आवश्यक है।”

मानवीय संसाधन विकास में शिक्षा निम्न प्रकार सहायता कर सकती है

- **योग्यताओं व क्षमताओं का विकास:** व्यक्ति में योग्यताओं व क्षमताओं को विकास करने का कार्य शिक्षा का ही है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, तथा उसकी योग्यताओं व क्षमताओं को विकसित कर बाहर निकाला जा सकता है।
- **चेतना का विकास:** शिक्षा मनुष्य को सचेत करती है। प्रत्येक व्यक्ति का समाज और राष्ट्रहित में जागरूक होना अति आवश्यक है। अतः शिक्षा, व्यक्ति को इस बात का अहसास करवाती है कि वह भी देश व समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है।
- **व्यवहार में परिवर्तन:** शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर उसे मानवीय गुणों से पोषित करती है, शिक्षा व्यक्ति के सोचने, समझने, तर्क देने, तुलनाकरने इत्यादि क्षमता का विकास करती है।
- **शिक्षा तथा उत्पादकता:** प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के समान अवसर सभी के लिए रोटी, कपड़ा व मकान की व्यवस्था, कृषि का विकास, उत्पादन क्षमता में वृद्धि यह सब शिक्षा के द्वारा ही संभव है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही लोगो की उत्पादक क्षमता का विकास तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कुशल जनशक्ति को तैयार करना है।
- **ज्ञान की प्राप्ति:** ज्ञान व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाता है जिससे वह मानसिक रूप से सजग व सचेत होता है प्रत्येक प्रकार के कार्य, व्यवसाय, रोजगार के लिए ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है।
- **तकनीकी कौशलों का विकास:** आधुनिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में नई-नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षा के द्वारा ही औद्योगिक व कृषि में विकास के लिए प्रयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीकों और कौशल का ज्ञान व्यक्ति को प्रदान करती है तथा तकनीकी कौशल का विकास करती है।
- **सामाजिकरण में सहायता:** समाज में रहकर व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, परम्पराओं, मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करता है और

यह उसे बेहतर ढंग से सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती करता है।

- **मानवीय पूंजी में वृद्धि:** शिक्षा द्वारा ही मानवीय पूंजी में वृद्धि की जा सकती है और इसके लिए शिक्षा एक सशक्त साधन के रूप में कार्य कर सकती है।
- **मूल्यों का विकास:** शिक्षा द्वारा मानवीय मूल्यों को विकसित करने में सहायता मिलती है। मानव संसाधन विकास के लिए सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तियों में इन गुणों का विकास किया जा सकता है।

भारत में मानवीय संसाधन विकास में निवेश:

भारत में मानवीय संसाधन गुणात्मक दृष्टि से उस स्तर के नहीं कहे जा सकते, जिस स्तर की तीव्र विकास के लिए आवश्यकता होती है। शिक्षित व प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव, कार्यशील जनसंख्या का निम्न अनुपात व कुपोषण तथा जीवनयापन की असंतोषजनक दशाओं के कारण उत्पादकता का निम्न स्तर आदि हमारे मानवीय साधनों की विशेषताएं हैं जो देश के विकास के मार्ग में बाधा का कार्य करते हैं। जब तक मानवीय संसाधन विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास भी संभव नहीं होगा। मानवीय संसाधनों के विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा व स्वास्थ्य पर किा गया विनियोग अत्यन्त कम है, जो कि निम्न सारणी से स्पष्ट है।

तलिक 1: भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा, तकनीकी व स्वास्थ्य पर व्यय (करोड रु.)

योजना	कुल योजना परिव्यय	शिक्षा व तकनीक	स्वास्थ्य	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
प्रथम योजना	1960	149	छ।	7 ^० 6
द्वितीय योजना	4672	273	छ।	5 ^० 8
तृतीय योजना	8577	660	226	10 ^० 3
तीन-वार्षिक योजनायें	6625	354	140	7 ^० 5
चतुर्थ योजना	15779	905	335	7 ^० 9
पांचवी योजना	39426	1710	761	6 ^० 3
छठी योजना	109292	3997	3412	6 ^० 8
सातवी योजना	218730	10709	3689	6 ^० 6
आठवी योजना	434100	28641	7576	8 ^० 3
नौवी योजना	859200	38840	5385	5 ^० 2
दसवी योजना	1525639	74786	12175	5 ^० 7
ग्यारहवी योजना	3750972	347338	174776	6 ^० 2

स्रोत: आर्थिक समीक्षा 2009-10 तथा भारत 2010

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा, तकनीकी एवं स्वास्थ्य पर किए गए व्यय से स्पष्ट है कि इस मद में प्रत्येक अगली योजना में व्यय विनियोग की राशि बढ़ने के बजाय घटती हुई है। सरकार का यह दृष्टिकोण उचित नहीं है, विशेषकर जबकि विकासवादी अर्थशास्त्रियों की राय में राष्ट्रीय आय का 30 से 40 प्रतिशत मानव संसाधन विकास पर अवश्य व्यय किया जाना चाहिए। भारत में वैज्ञानिकों एवं प्राविधिकों की संख्या भी विकसित देशों की तुलना में कम है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत हो गयी है।

भारत में बाहरवी योजना में कुल परिव्यय की राशि 84,86,226 करोड रुपये प्रस्तावित की गई, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं और विशेष रूप से महिलाओं एवं बाल स्वास्थ्य की योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। इसके लिए स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन में वृद्धि की बात कही गयी। इसके अतिरिक्त शिक्षा एवं दक्षता विकास के लिए उच्च शिक्षा को सुदृढ करने के लिए सघन प्रयाय किये गये।

भारत में शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर कुल योजना परिव्यय का मात्र 10 से 15 प्रतिशत के बीच व्यय किया जाता है। यह मानव संसाधन विकास की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। अमेरिका का, इंग्लैण्ड तथा जर्मनी में मानव संसाधन विकास पर देश के कुल परिव्यय का क्रमशः 47 प्रतिशत, 49 प्रतिशत तथा 63 प्रतिशत व्यय किया जाता है। भारत में वर्ष 2013 में केन्द्र सरकार द्वारा कुल परिव्यय का 11.7 प्रतिशत शिक्षा एवं कौशल विकास पर तथा 4.8 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय किया गया।

वर्तमान में देश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। देश में स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है जिसके फलस्वरूप देश में अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा इन अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों तथा नर्सों की संख्या में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है।

वर्ष 2006-2010 में देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 66.1 वर्ष शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हजार, जन्मदर 21.8 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार थी। इसके बावजूद यदि विकसित देशों से तुलना की जाए तो यहां अभी भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू0एन0डी0पी0) (जो दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन जीने, शिक्षित और सुविज्ञ होने और जीवन यापन के अच्छे आर्थिक मानक, देश अभी भी जीवन प्रत्याशा तथा प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति की दृष्टि से बहुत पीछे है, जिसके फलस्वरूप यहां एच0डी0आई0 में सम्मानजनक वृद्धि नहीं हो पा रही है। मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार 2011 में भारत का मानव विकास सूचकांक 0.547 था। मानव विकास रिपोर्ट 2011 में भारत का विश्व में 187 देशों की सूची में एच0डी0आई0 रैंक 134वां था जबकि निकटवर्ती देशों में चीन का 101वां और श्रीलंका का 97वां स्थान है। पाकिस्तान का 145, बांग्लादेश का 146 एवं नेपाल का 157वां स्थान है, जबकि मानव विकास सूचकांक में विश्व के पांच प्रथम देशों का सूचकांक 1-नार्वे (0.943), 2-आस्ट्रेलिया (0.929), 3-नीदरलैण्ड (0.910), 4-संयुक्त राज्य अमेरिका (0.910) तथा 5-न्यूजीलैण्ड (0.908) है।

निःसंदेह भारत में मानवीय पूंजी-निर्माण अभी भी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है, देश के तीव्र आर्थिक विकास का स्वप्न तब तक साकार नहीं हो सकता, जब तक कि स्वस्थ नागरिकों, कुशल कर्मचारियों, प्रशिक्षकों, वैज्ञानिकों, प्राविधिकों तथा प्रशासकों का देश में उच्च स्तर पर निर्माण नहीं हो जाता। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यू0जी0सी0 का इस सम्बन्ध में कहना है कि "भारत प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से पूर्णतया सम्पन्न देश है और इसके नागरिक प्रतिभाशाली एवं शक्तिवान हैं उनमें विकास एवं पुनर्निर्माण की उत्कृष्ट अभिलाषा विद्यमान है"-सवाल है तो केवल उसे गति एवं व्यावहारिक रूप देने का और यह उत्तरदायित्व अब विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थाओं का है कि वे ज्ञान का सृजन करके नूतन मस्तिष्कों को प्रशिक्षित करें, ताकि प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का समन्वित एवं सन्तुलित ढंग से उपयोग किया जा सके।

यह अत्यंत खेदका विषय है कि भारत में मानवीय संसाधनों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। आज भारत में मानव विकास को प्रोन्नत करने की अत्याधिक आवश्यकता है। अतः सरकार को शिक्षा व स्वास्थ्य में विनियोग करना होगा। हमारी शिक्षा का दुखद पहलू यह है कि देश में शिक्षा के माध्यम से जो मानव शक्ति का निर्माण किया जा रहा है वह हमारी आर्थिक विकास की योजनाओं के अनुरूप नहीं है। मानवीय संसाधन विकास को उन्नत करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य से सम्बन्धित सुविधाओं और सेवाओं में निवेश करना अनिवार्य तथा आवश्यक है। इसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार की

अर्थपरक सोच उच्च शिक्षा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से उच्च शिक्षा पर की जाने वाली निवेश की राशि लगातार घटती जा रही है, जबकि निवेश बढ़ाकर अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आज यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्र की सुदृढता व विकास के लिए शिक्षा की संरचना में पुनः सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। आर्थिक स्वतंत्रता के इस प्रतिस्पर्धी युग में हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो मानवीय संसाधनों का विकास देश की आवश्यकताओं के अनुरूप करे।

संदर्भ

1. योजना मार्च 2006
2. डा0 एस0पी0 सिंह "आर्थिक विकास एवं नियोजन"
3. वी0के0पुरी, एस0के0 मिश्र "भारत अर्थ व्यवस्था"
4. लक्ष्मीकान्त नाथरामका "भारतीय अर्थ व्यवस्था बदलता परिदृश्य"
5. जे0सी0 पन्त "भारतीय आर्थिक समस्याएँ"
6. डा0 जे0पी0 मिश्रा "अल्प विकसित देशों का अर्थशास्त्र"
7. वी0सी0 सिन्हा "आर्थिक संवृद्धि और विकास"
8. www.zigya.com>stud>book
9. www.atpeducation.com
10. <https://hi.m.wikipedia.org>